

गृहमंत्री शाह का नशे के खिलाफ देशव्यापी अभियान, मोटरसाइकिल रैली की रवाना

संवाददाता
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गृहमंत्री ने 'नशे के खिलाफ लड़ाई' का संदेश देने वाली देशव्यापी मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में संसद सदस्य कृष्ण प्रसाद टेनेटी, राजीव कुमार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक महेश दीक्षित, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर सहित अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के महानिदेशक और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद करीब आठ दशकों में देश आज विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर खड़ा है। इसकी नींव में हमारे वीर जवानों का बलिदान है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यदि इन जवानों ने आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान न दिया होता, तो आज हम कहाँ खड़े होते। गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 भारतीय पुलिस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। 31 मार्च 2026 को हमने दशकों से देश को पीड़ित कर रहे नक्सलवाद



से मुक्ति प्राप्त की। नक्सलवाद के कारण 1981 से मार्च 2026 तक देश ने अनेक दर्श झेले हैं। इस समयावधि में 3600 से अधिक जवान शहीद हुए और देश के लगभग 13,700 निर्दोष नागरिक भी अपनी जान गँवा बैठे। गृहमंत्री ने कहा कि वे शहीद जवानों के परिजनों को बताना चाहते हैं कि पांच दशक पुरानी इस समस्या से निजात पाकर यदि देश आज विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो इसकी नींव में इन 3600 जवानों का बलिदान है। गृहमंत्री ने शहीदों के परिजनों से कहा कि हम आपकी क्षति की पूर्ति नहीं कर सकते, परंतु 140 करोड़ नागरिकों वाला पूरा देश आपके परिवार के समर्पण के प्रति कृतज्ञ है। अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के दुर्गम हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 10 जवानों ने चीन की सेना के हमले

का डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। जब हम हॉट स्प्रिंग्स की उस घटना का अध्ययन करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि जब संघर्ष का निर्णय ऊंची पहाड़ियों पर लिया गया होगा, तब परिणाम लगभग तय था। फिर भी उन अमर सपूतों ने देश की एक इंच भूमि भी किसी विदेशी के हाथ में न जाए, इस संकल्प को मृत्यु पर्यन्त निभाते हुए अपना अमर बलिदान दिया। तभी से 21 अक्टूबर का यह दिन प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गृहमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में देश में कई समस्याएं थीं, जिनमें तीन प्रमुख समस्याओं को हम दशकों से झेल रहे थे। कश्मीर, उत्तर-पूर्व और लाल आतंक का पूरा क्षेत्र- इन तीनों हॉटस्पॉट में आज शांति है, विकास का वातावरण बना है और ये सभी क्षेत्र देश के साथ विकास की संघर्ष में भागीदारी करने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने कहा कि देश समस्याओं से पूर्णतः

मुक्त नहीं हुआ है। हमारे सामने अभी भी कई समस्याएं हैं। गृह मंत्रालय ने तय किया है कि वर्ष 2026 के शेष भाग तथा 2027, 2028 एवं 2029 - इन साढ़े तीन वर्षों में हम ड्रग्स के खिलाफ एक संयुक्त लड़ाई लड़कर 31 दिसंबर 2029 तक देश को ड्रग की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की समस्या हमारी आने वाली पीढ़ियों को खोखला करती है। हमारे अर्थतंत्र पर अनावश्यक बोझ डालती है और देश विरोधी प्रवृत्तियाँ रखने वाले संगठनों को आर्थिक समर्थन भी प्रायः ड्रग तस्करों से ही मिलता है। गृहमंत्री ने देशभर के पुलिस बलों का आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तैयार किए गए 'नशा मुक्त भारत' के रोडमैप को जमीन पर उतारने के लिए पूरे मनोयोग से जुड़ें और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करें। उल्लेखनीय है कि गृहमंत्री की ओर से रवाना की गई मोटरसाइकिल रैली में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली), केंद्रीय सशस्त्र बलों (सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी व एनएसजी) और कुछ केंद्रीय पुलिस संगठनों (आरपीएफ, एनटीआरएफ व एनआईए) के लगभग 90 सवार शामिल हैं।

'टीवी चैनल आतंकवाद-रोधी अभियानों की लाइव कवरेज से बचे'

संवाददाता
नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए बुधवार को एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वे आतंकवाद-रोधी अभियानों की लाइव कवरेज से बचें, भड़काऊ बहस और राष्ट्रविरोधी सामग्री न दिखाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। मंत्रालय ने एडवाइजरी में सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों को कार्यक्रम संहिता का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि उनकी अंतर-विभागीय समिति ने पाया है कि चैनलों पर प्रसारित खबरें और दृश्य संहिता के अनुरूप नहीं हैं और एक ही तरह के दृश्य बार-बार दिखाए जा रहे हैं। आदेश के मुताबिक आतंकवाद विरोधी अभियानों का लाइव कवरेज पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ऑपरेशन समाप्त होने तक केवल अधिकृत अधिकारी की ब्रीफिंग ही प्रसारित की जा सकेगी। नए दृश्यों पर टाइम-स्टैम्प लगाना अनिवार्य होगा।



हिंसक और परेशान करने वाले दृश्यों को लेकर भी चैनलों को सतर्क रहने को कहा गया है। ऐसे दृश्यों को लूप में बार-बार न दिखाने और जरूरत पड़ने पर ब्लर या मारिक्ग का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। अपराध से जुड़ी खबरों में सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचने और सत्यापित तथ्यों पर आधारित कवरेज करने को कहा गया है। टीवी चैनलों को महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं और हादसों की रिपोर्टिंग में टाइम-स्टैम्प का इस्तेमाल अनिवार्य होगा, ताकि दर्शकों में दहशत न फैले। मंत्रालय ने सभी चैनलों को केवल भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित भारत के प्रामाणिक मानचित्र का ही उपयोग करने का आदेश दिया है।

सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत, सात दिन बाद जेल से रिहाई का आदेश

■ दिल्ली पुलिस ने तीन दिन और न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, एसईएम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी राहत

संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली की स्पेशल एजिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) अदालत ने बुधवार को कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों पिछले सात दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उनकी न्यायिक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बाद में अदालत ने दोनों को रिहा करने का आदेश दिया। दोनों नेताओं को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से बैरिकेडिंग पार कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने और नारेबाजी करने के मामले में हिरासत में लिया गया



था। 13 अक्टूबर को उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई थी। सीजेपी नेताओं पर आरोप था कि उन्होंने पहले से दिए गए शांति संबंधी बॉन्ड की शर्तों को उल्लंघन किया। पुलिस का कहना था कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए अधिसूचित स्थानों की सूची से हटाए जाने के बावजूद दोनों वहां पहुंचे और बैरिकेडिंग पार की। सीजेपी की ओर से इस कार्रवाई को विरोध की आवाज दबाने का प्रयास बताया गया था। मामले में तीसरे नेता अजिंक्य शिंदे को पहले नया बेल बॉन्ड भरने के बाद राहत मिल चुकी थी। वहीं सौरव दास

और आशुतोष रांका ने अपनी हिरासत को दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने नेताओं की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार से जोड़ा था। दूसरी ओर पुलिस का तर्क था कि प्रतिबंधित स्थान पर प्रवेश और पूर्व बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई की गई। सीजेपी और अन्य विपक्षी समूह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने पक्षपात और अनियमितता के आरोपों को खारिज किया है। एसईएम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे समेत तीनों को ट्रांजिड रिमांड

संवाददाता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में उत्तर प्रदेश की पुलिस और स्पेशल टॉस्क फोर्स की टीम को कामयाबी मिली है। टीम की पेश रिपोर्ट के आधार नागपुर की जिला और सब न्यायालय ने मुख्य आरोपित आशु दुबे उसकी बहन रश्मि दुबे और झावर दानिश को ट्रांजिड रिमांड पर भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने बुधवार को बताया कि नौ अक्टूबर को हुई गंभीर घटना के मुख्य आरोपितों को लखनऊ पुलिस और एसटीएफ की टीम ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। आज उन्हें नागपुर की कोर्ट में पेश कर ट्रांजिड रिमांड के लिए अर्जी दी। न्यायालय ने रिमांड स्वीकार कर लिया है। आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ लाया जा रहा है। सभी साक्ष्यों के आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी। अपराध में किसी भी प्रकार से संलिप्त कोई भी व्यक्ति बच नहीं पायेगा। न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ की



टीमें अब तीनों आरोपितों को सड़क मार्ग से लखनऊ ला रही हैं। गुरुवार दोपहर तक सभी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इन तीनों आरोपितों पर 50 -50 हजार रुपये इनाम घोषित किया था। उल्लेखनीय है कि कैफे संचालक शिवा शर्मा का शव 9 अक्टूबर को लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट में शव मिला था। यह फ्लैट श्रद्धा दुबे का है। मृतक शिवा का मां रंजना शर्मा ने बेटी की हत्या का आरोप उसकी लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे पर लगाया था। वहीं, श्रद्धा दुबे अपनी बहन, झावर के साथ घटना के बाद से ही फरार थी। उसे नेपाल में देखे जाने की बात सामने आई। वहीं मामला हाईप्रोफाइल होने पर एसीपी हरतरंग जूनीश वर्मा को हटा दिया गया था। इसके अलावा इंस्पेक्टर भी बदले गये थे।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच सीमा शुल्क सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता

संवाददाता
नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार को सुगम बनाने और सीमा शुल्क संबंधी सहयोग मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में उत्पत्ति संबंधी आंकड़ों (डेटा ऑफ ओरिजिन) के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान पर समझौता किया है। इस व्यवस्था के तहत दोनों देश व्यापारिक वस्तुओं के मूल देश से संबंधित आंकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान करेंगे। इससे सीमा पार व्यापार की प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय आयातक कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा (एनजेडसीएस) के बीच समझौता 19 अक्टूबर को हुआ। इस पर सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क

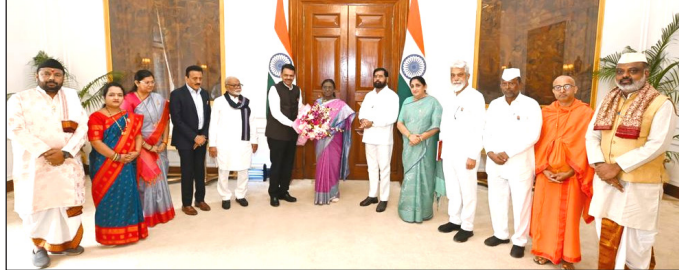


सेवा की नियंत्रक एवं मुख्य कार्यकारी क्रिस्टीन स्टीवेन्सन ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत किया गया है। दोनों देशों के बीच एफटीए 20 अक्टूबर से लागू हो गया है। इस समझौते का उद्देश्य सीमा शुल्क से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान को बेहतर बनाना और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना

है। समझौते के तहत वस्तुओं के मूल देश से संबंधित आंकड़ों का अग्रिम इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान किया जा सकेगा। इससे दोनों देशों के सीमा शुल्क विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा और व्यापार से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध हो सकेगी। इससे सूचनाओं की कमी दूर करने और सीमा पार व्यापार की प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सिंहस्थ कुंभ के ध्वजारोहण समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण

■ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात
■ गोदा आरती, वेबसाइट, कुंभ गीत, कॉफी टेबल बुक और डाक टिकट के अनावरण का भी न्योता



संवाददाता
नई दिल्ली/मुंबई। नाशिक-त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के महत्वपूर्ण पर्व के ध्वजारोहण समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को औपचारिक निमंत्रण दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात की। इस अवसर

पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने राष्ट्रपति को नाशिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण सौंपा। साथ ही महाराष्ट्र की आध्यात्मिक परंपरा, आदिवासी उद्यमिता, वस्त्रकला, कृषि समृद्धि और खाद्य संस्कृति की विविधता को दर्शाने वाला विशेष उपहार-संग्रह भी भेंट किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को ध्वजारोहण के दिन प्रस्तावित गोदावरी आरती, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला प्राधिकरण की वेबसाइट के उद्घाटन, कुंभ मेले के आधिकारिक गीत के लोकार्पण, कुंभ मेले पर

आधारित कॉफी टेबल बुक तथा विशेष डाक टिकट के अनावरण के लिए भी आमंत्रित किया। नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियां राज्य सरकार और नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला प्राधिकरण के स्तर पर चल रही हैं। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, सिंहस्थ कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए विभिन्न विभागों को बुनियादी ढांचे, पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, प्रचार और अन्य कार्यों के लिए प्रशासनिक मंजूरीयां दी गईं हैं। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा

उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन एवं कुंभ मेला मंत्री तथा नाशिक के पालकमंत्री गिरीश महाजन, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा विशेष सहायता मंत्री नरहरी झिरवाठ भी उपस्थित थे। इसके अलावा नाशिक की महापौर हिमगौरी आडके-आहरे, त्र्यंबक नगर परिषद की नगराध्यक्षा त्रिवेणी तुंगार, त्र्यंबकेश्वर देवस्थान के अध्यक्ष एवं धर्मादाय सह आयुक्त न्यायमूर्ति विवेक सोनुणे सहित अन्य अधिकारी और पदाधिकारी भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे। नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला प्राधिकरण को महाराष्ट्र सिंहस्थ कुंभ मेला अधिनियम, 2025 के तहत आयोजन, प्रबंधन, बजट और समन्वय से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शीघ्र समिति समेत विभिन्न समितियां भी गठित की हैं।

संपादकीय

परिसीमन और लोकतंत्र

भारत में लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक को प्रतिनिधित्व की समान भावना मिले और चुनावी व्यवस्था पर उसका विश्वास बना रहे। इसी संदर्भ में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं तथा प्रतिनिधित्व का निर्धारण करना है। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संघीय संतुलन और लोकतांत्रिक विश्वसनीयता से जुड़ा विषय है। परिसीमन की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। समय के साथ जनसंख्या का वितरण बदलता है, शहरों का विस्तार होता है और अनेक क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ती है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्रों के बीच मतदाताओं की संख्या में असमानता प्रतिनिधित्व के सवाल खड़े कर सकती है। यदि एक क्षेत्र का सांसद लाखों अधिक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, तो समान प्रतिनिधित्व की अवधारणा पर बहस होना स्वाभाविक है। इसलिए परिसीमन की प्रक्रिया में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों और वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हालांकि, भारत में परिसीमन का प्रश्न केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण करने तक सीमित नहीं है। देश की संघीय व्यवस्था में राज्यों की भूमिका और उनके बीच राजनीतिक संतुलन भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के कई राज्यों ने लंबे समय तक जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए हैं। ऐसे में उनकी चिंता है कि यदि भविष्य में संसदीय सीटों का निर्धारण केवल जनसंख्या के अनुपात में किया गया, तो उनकी संसद में सापेक्ष हिस्सेदारी कम हो सकती है। दूसरी ओर, अधिक आबादी वाले राज्यों का तर्क है कि उनके नागरिकों को भी समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करना सरकार और संसद के सामने बड़ी चुनौती है। अप्रैल 2026 में परिसीमन से संबंधित विधेयक संसद में आवश्यक समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। इस घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया कि परिसीमन जैसे व्यापक संवैधानिक विषय पर केवल संख्याबल के आधार पर आगे बढ़ना आसान नहीं है। महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के तरीके पर भी राजनीतिक मतभेद सामने आए। सरकार ने प्रतिनिधित्व के विस्तार और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि विपक्ष ने प्रस्तावित प्रक्रिया, जनगणना और राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित चिंताएं उठाईं। इन मतभेदों का समाधान आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि तथ्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और व्यापक संवाद से निकलना चाहिए। लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए यह भी आवश्यक है कि परिसीमन की प्रक्रिया पारदर्शी हो। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के मानदंड स्पष्ट हों, संबंधित राज्यों और राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने का अवसर मिले तथा आम नागरिकों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए। परिसीमन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। किसी भी क्षेत्र को राजनीतिक लाभ या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सीमाओं में बदलाव किए जाने की आशंका भी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से दूर की जानी चाहिए। महिला आरक्षण का विषय भी इस बहस से जुड़ा हुआ है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मतदाता सूची से नाम हटने की पीड़ा और हाशिए पर खड़ा आम आदमी

महेन्द्र तिवारी

लोकतंत्र में मतदान केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि नागरिक की पहचान, सम्मान और भागीदारी का प्रतीक है। जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि मतदाता सूची से उसका नाम हटा दिया गया है, तो यह उसके लिए केवल एक प्रशासनिक त्रुटि नहीं होती, बल्कि अपने ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपेक्षित हो जाने की पीड़ा भी होती है। जिस नागरिक ने वर्षों तक मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत किया, अचानक उसी को अपनी नागरिक भागीदारी साबित करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, तो उसकी बेबसी समझी जा सकती है। हाल के दिनों में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की खबरों ने इस प्रश्न को गंभीर बना दिया है। समाचारों के अनुसार, अनेक लोगों को सूची से नाम हटने के बाद दोबारा पंजीकरण कराने और अपनी पात्रता साबित करने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में भी लाखों मतदाताओं के नामों के पुनः सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने की खबर सामने आई है। निर्वाचन संबंधी अभिलेखों को शुद्ध रखना आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी योग्य नागरिक का नाम गलती से हट जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस समस्या का सबसे अधिक प्रभाव समाज के कमजोर और वंचित वर्गों पर पड़ता है। दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति एक दिन काम छोड़कर सरकारी कार्यालय जाता है, तो उसके परिवार की आमदनी प्रभावित होती



है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों, प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों और अशिक्षित नागरिकों के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाना तथा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना आसान नहीं होता। जिनके पास पर्याप्त समय, संसाधन और प्रशासनिक जानकारी है, वे अपनी समस्या के समाधान का रास्ता खोज लेते हैं, लेकिन हाशिए पर खड़ा व्यक्ति अक्सर व्यवस्था की जटिलताओं के सामने असहाय हो जाता है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है, जब वर्षों से मतदान करते आ रहे किसी व्यक्ति को अचानक अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। कहीं किसी जीवित व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है, तो कहीं स्थान परिवर्तन या अभिलेखों की त्रुटि के कारण नाम सूची से गायब हो जाता है। निर्वाचन आयोग के अपने दिशा-निर्देश भी नाम हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया, आवश्यक सत्यापन और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने पर बल देते हैं। इसलिए प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जाँच और समयबद्ध समाधान आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना होगा कि मतदाता सूची की

सौरभ वार्णाय

वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलते समीकरणों के बीच भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर सामने आए सकारात्मक संकेत दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह कहना कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अब कुछ ही मुद्दों पर काम बाकी है और जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है, इस दिशा में आगे बढ़ती बातचीत का संकेत देता है। हालांकि, किसी भी समझौते की वास्तविक सफलता केवल उसकी घोषणा या हस्ताक्षर से नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले आर्थिक लाभ, व्यापारिक संतुलन और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा से तय होती है। इसलिए भारत को इस समझौते की संभावनाओं के साथ-साथ उसकी चुनौतियों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में अनेक क्षेत्रों में विस्तारित हुए हैं। रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा, निवेश और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति जैसे विषयों पर दोनों देश लगातार सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में व्यापार समझौते को लेकर बनी सहमति की संभावना आर्थिक संबंधों को नई गति दे सकती है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि भारत और अमेरिका की आर्थिक प्राथमिकताएं, औद्योगिक संरचना और घरेलू बाजार का आवश्यकताएं एक-दूसरे से अलग हैं। इसलिए समझौते की दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों पक्षों को ऐसा संतुलन बनाना होगा, जिससे सहयोग बढ़े और किसी एक देश के हित दूसरे की कोमत पर प्रभावित न हो। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संकेत दिया कि भारत और अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। उनके अनुसार, कुछ मुद्दों पर काम बाकी है और जल्द औपचारिक घोषणा की उम्मीद की जा सकती है। इससे पहले भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी समझौते के पहले चरण को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद जता चुके हैं। इन बयानों से स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की राजनीतिक और कूटनीतिक इच्छा मौजूद है। फिर भी, जब तक समझौते की शर्तों, दायरे और समयसीमा को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक इसके संभावित परिणामों के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। व्यापार समझौते का उद्देश्य सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को आसान बनाना, शुल्क संबंधी बाधाओं को कम करना, निवेश को प्रोत्साहित करना तथा



कारोबारियों के लिए बाजार तक पहुंच बेहतर करना होता है। भारत और अमेरिका के बीच ऐसा सहयोग मजबूत होता है तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अधिक अवसर मिल सकते हैं। दूसरी ओर, अमेरिकी कंपनियों को भी भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि इन अवसरों का लाभ किसे और कितना मिलेगा? क्या भारतीय छोटे और मध्यम उद्योगों को भी इससे फायदा पहुंचेगा, या लाभ मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों तक सीमित रह जाएगा? समझौते का मूल्यांकन इन प्रश्नों के आधार पर होना चाहिए। अमेरिका दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसका बाजार भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। कपड़ा, परिधान, औषधि, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। अनुकूल व्यापारिक शर्तें इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ा सकती हैं। यदि भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलती है, तो निर्यात में वृद्धि की संभावना बनेगी। इससे उत्पादन बढ़ सकता है, नई इकाइयों में निवेश आकर्षित हो सकता है और रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकते हैं। विशेष रूप से श्रम आधारित उद्योगों के लिए विदेशी बाजारों का विस्तार महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात की वृद्धि का सीधा संबंध रोजगार से हो सकता है। हालांकि, केवल बाजार तक पहुंच मिलना पर्याप्त नहीं है। भारतीय उद्योगों को गुणवत्ता, लागत, तकनीकी दक्षता, समय पर आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय को मानकों के अनुरूप उत्पादन की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। सरकार को व्यापार समझौते के साथ-साथ घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सस्ता ऋण, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, बेहतर लॉजिस्टिक्स और निर्यात संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। यदि छोटे उद्यमों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार

के नए अवसरों का लाभ बड़े कारोबारियों तक सीमित रहने की आशंका बनी रहेगी। भारत और अमेरिका के बीच किसी भी व्यापार समझौते का सबसे संवेदनशील पक्ष कृषि और खाद्य क्षेत्र हो सकता है। भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। छोटे और सीमांत किसानों की आय, उत्पादन लागत, फसलों के उचित मूल्य तथा ग्रामीण रोजगार जैसे प्रश्न देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता से जुड़े हैं। अमेरिका में कृषि उत्पादन का बड़ा हिस्सा आधुनिक तकनीक, व्यापक कृषि भूमि और विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता से जुड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों देशों के कृषि उत्पादकों की लागत और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति अलग हो सकती है। यदि किसी समझौते के तहत संवेदनशील कृषि उत्पादों के आयात पर बाधाएं कम की जाती हैं, तो भारतीय किसानों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ने की आशंका मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कृषि व्यापार को पूरी तरह सीमित कर दिया जाए। कृषि उत्पादों का व्यापार दोनों देशों के लिए अवसर पैदा कर सकता है। लेकिन भारत को खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। संवेदनशील उत्पादों के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय, स्पष्ट नियम और घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा आवश्यक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आर्थिक लाभ और सामाजिक दायित्व के बीच संतुलन बनाए। व्यापार समझौता ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे निर्यात बढ़ाने की उम्मीद में घरेलू किसानों और छोटे उत्पादकों की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाए। मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की बैठक में ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में बातचीत को महत्वपूर्ण बताया। यह तथ्य रेखांकित करता है कि भारत-अमेरिका संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापक रणनीतिक महत्व रखते हैं।

भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता, तकनीकी सहयोग और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना भारत की दीर्घकालिक आर्थिक आवश्यकताओं से जुड़ा है। इसी प्रकार रक्षा क्षेत्र में सहयोग से आधुनिक तकनीक, उपकरणों के उत्पादन और औद्योगिक साझेदारी के अवसर बन सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में सहयोग भी विशेष महत्व रखता है। डिजिटल सेवाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी भारत के विकास लक्ष्यों को समर्थन दे सकती है। हालांकि, तकनीकी सहयोग के साथ डेटा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा, घरेलू क्षमता निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। भारत को किसी भी साझेदारी में अपनी स्वतंत्र निर्णय क्षमता

बनाए रखते हुए सहयोग के अवसरों का उपयोग करना चाहिए। मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अर्थ केवल किसी बड़े साझेदार के साथ निकटता नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र और संतुलित नीति अपनाना भी है। व्यापार समझौते की घोषणा निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत दे सकती है, लेकिन उसकी सफलता का आकलन ठोस परिणामों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। क्या इससे भारतीय निर्यात में वास्तविक वृद्धि होगी? क्या निवेश बढ़ेगा? क्या रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे? क्या छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा? और क्या भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों की पर्याप्त सुरक्षा कर पाएगा? ये वे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर समझौते की शर्तें स्पष्ट होने के बाद ही मिल सकेंगे। सरकार को समझौते से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को पारदर्शी तरीके से सामने लाना चाहिए।



एल.आई.सी

भारतीय जीवन बीमा

से संबंधित किसी भी

जानकारी या समस्या

समाधान हेतु संपर्क करें।

-भारत सिंह

मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जाँचना संभव नहीं है।

ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए दैनिक स्वर्णिम प्रदेश के अंतर्गत समाचार पत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियों, संस्थाएं या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।

आज का राशिफल



मेघ: दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। नौकरी में संतोष रहेगा। निवेश शुभ रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। घर में अतिथियों का आमनन होगा। व्यव होगा। विरोध होगा। विवाद से क्लेश होगा, इससे बचें। पुराना रोग उभर सकता है।

वृषभ: व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। निवेश मनोनुकूल लाभ देगा। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। शत्रु सक्रिय रहेंगे। शारीरिक कष्ट संभव है। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करें।

मिथुन: परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। तनाव रहेगा। पुराना रोग उभर सकता है। लेन-देन में सावधानी रखें। किसी भी व्यक्ति की बातों में न आएँ। महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें, लाभ होगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आएँगे। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें।

कर्क: कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे बाद में पछताना पड़े। जोखिम न लें। बोलचाल में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। प्रतिद्वंद्विता कम होगी। शत्रु सक्रिय रहेंगे। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें।

सिंह: जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। शेर मार्केट से लाभ होगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। भाग्य का साथ रहेगा। सभी काम पूर्ण होंगे। जल्दबाजी न करें। कोर्ट व कचहरी में लंबित कार्य पूरे होंगे।

कन्या: नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। शेर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें। संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं। झंझटों से दूर रहें। घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी। रोजगार में वृद्धि तथा बेरोजगारी दूर होगी। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। संचित कोष में वृद्धि होगी।

तुला: विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा। व्यापार मनोनुकूल रहेगा। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। लाभ के अवसर हाथ आएँगे। व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रमाद न करें। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा लाभदायक रहेगी।

वृश्चिक: प्रयास अधिक करना पड़ेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में कमी रह सकती है। दुःखद समाचार की प्राप्ति संभव है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा। बेवजह विवाद की स्थिति बन सकती है। दूसरों के उकसाने में न आकर महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लें, लाभ होगा।

धनु: जल्दबाजी में कोई काम न करें। पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। कोई आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है। चिंता तथा तनाव रहेंगे। कुंआरों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। प्रयास सफल रहेंगे। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में उन्नति होगी। व्यापार लाभदायक रहेगा। प्रमाद न करें।

मकर: व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। कारोबार में मनोनुकूल लाभ होगा। प्रमाद न करें। किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी न करें। भ्रम की स्थिति बन सकती है। लेन-देन में सावधानी रखें। थकान व कमजोरी महसूस होगी।

कुंभ: घर-बाहर सहयोग प्राप्त होगा। भेंट व उपहार की प्राप्ति संभव है। बेरोजगारी दूर होगी। अचानक कहीं से लाभ के आसार नजर आ सकते हैं। किसी बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। निवेश व नौकरी मनोनुकूल लाभ देंगे। अप्रत्याशित खर्च सामने आएँगे। कर्ज लेना पड़ सकता है।

मीन: धनलाभ के अवसर हाथ आएँगे। सामाजिक कार्य करने में रुचि रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। जोखिम उठाने का साहस कर पाएँगे। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। कार्यसिद्धि होगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। बेचैनी रहेगी। प्रयास सफल रहेंगे।

संभावित जलसंकट से निपटने के लिए 25 अक्टूबर तक गांववार कार्ययोजना तैयार करें: मंत्री गुलाबराव पाटील

संवाददाता

मुंबई। जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील ने नागपुर, अमरावती और कोकण विभागों में संभावित जलसंकट को देखते हुए सभी चरणों की वस्तुनिष्ठ और गांववार कार्ययोजना 25 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 75 से 99 प्रतिशत तक प्राप्ति कर चुकी जलापूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा कर चालू करने को कहा है। बुधवार को सप्ताद्री अतिथिगृह में आयोजित समीक्षा बैठक में नागपुर, अमरावती और कोकण विभागों की जलापूर्ति योजनाओं, भूजल स्तर और आने वाले महीनों में संभावित पानी की कमी से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। मंत्री पाटील ने कहा कि फिलहाल इन चरणों में गंभीर जलसंकट नहीं है, लेकिन प्रशासन को संभावित स्थिति को देखते हुए अभी से तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों, सरपंचों और ग्राम पंचायतों से चर्चा कर तथा मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति पर आधारित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत ऑरिम चरण में पहुंच चुकी योजनाओं में पाइपलाइन, पंप, बिजली कनेक्शन और ट्रांसफार्मर जैसे लंबित कार्य तत्काल पूरे करने को कहा गया। मंत्री पाटील ने कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति वाली योजनाओं की पैकेज संबंधी जानकारी पूरी कर प्रमाणित की जाए, ताकि निधि वितरण में कोई अड़चन न आए। संभावित टैंकर प्रभावित गांवों के लिए जलस्रोत मजबूत करने की अलग

जल जीवन मिशन की 75 से 99 फीसदी पूरी योजनाओं को प्राथमिकता से चालू करने के निर्देश, टैंकर को बताया अंतिम विकल्प



कार्ययोजना भी तैयार की जाए। उन्होंने जिला नियोजन समिति के दो प्रतिशत निधि प्रावधान से जलस्रोत सुदृढ़ीकरण के काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इसके तहत कुओं का पुनर्भरण, खेत तालाब, सीमेंट बंधारे, सीमेंट प्लाग, लगातार समतल चर और पुराने बंधारों की मरम्मत जैसे काम किए जाएं। जरूरत के अनुसार जिला नियोजन, खनिज निधि और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि से भी कामों की योजना बनाने को कहा गया। मंत्री पाटील ने स्पष्ट किया कि पानी की कमी दूर करने के लिए टैंकर अंतिम विकल्प होना चाहिए। इससे पहले उपलब्ध कुओं की सफाई और कीटाणुशोधन, स्थानीय जलस्रोतों का पुनर्जीवन, जलापूर्ति का बेहतर नियोजन और पानी के मितव्ययी उपयोग जैसे उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी गांव से जलसंकट की शिकायत मिलने या इस संबंध में समाचार प्रकाशित होने पर संबंधित अधिकारी तत्काल गांव का दौरा कर आवश्यक कार्रवाई करें। बैठक में

लॉन्ड्री व्यवसायियों को बिजली बिल में 30 प्रतिशत सब्सिडी लागू करने की मांग

हादी अली शैख

मुंबई। महाराष्ट्र में पारंपरिक लॉन्ड्री व्यवसाय से जुड़े रजक (धोबी) समाज के सामने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों को लेकर रजक महासंघ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप की मांग की है। महासंघ ने पत्र लिखकर कहा है कि लॉन्ड्री व्यवसायियों के लिए बिजली बिल में निर्धारित 30 प्रतिशत सब्सिडी के शासनादेश को पूरे राज्य में समान रूप से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। रजक महासंघ के अध्यक्ष दशरथ कर्नौजिया की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बड़ी संख्या में रजक परिवार दशकों से लॉन्ड्री व्यवसाय पर निर्भर हैं और बिजली इस काम का अनिवार्य हिस्सा है। बढ़ते बिजली बिल के कारण छोटे लॉन्ड्री व्यवसायियों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। महासंघ ने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्ष 2017 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के प्रयासों से लॉन्ड्री व्यवसायियों को बिजली बिल में 30 प्रतिशत सब्सिडी देने का शासनादेश जारी किया गया था। महासंघ को चकना है कि इस निर्णय से हजारों परिवारों को राहत मिली थी, लेकिन बाद के



वर्षों में राज्य के कई हिस्सों में इसका क्रियान्वयन समान रूप से नहीं हो रहा है। महासंघ का आरोप है कि कुछ बिजली वितरण कंपनियों और स्थानीय स्तर के अधिकारियों की उदासीनता के कारण पात्र लॉन्ड्री व्यवसायियों को सब्सिडी का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। इससे छोटे व्यवसायियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। रजक महासंघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य की सभी सरकारी और निजी बिजली वितरण कंपनियों को शासनादेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही, आदेश के पालन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की स्पष्टता भी की जाए। महासंघ ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप कर पारंपरिक लॉन्ड्री व्यवसायियों को राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

त्योहारों के बीच महाराष्ट्र FDA की बड़ी कार्रवाई: करोड़ों रुपये के खाद्य पदार्थ जब्त

तेल, पनीर, खवा, फरसाण, चाय और प्रतिबंधित पानमसाला-तंबाकू पर छापे, कई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

संवाददाता

मुंबई। त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन (FDA) ने पिछले तीन दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में विशेष अभियान चलाते हुए खाद्य तेल, पनीर, खवा, मिठाइयों, फरसाण, चाय और प्रतिबंधित पानमसाला-सुगंधित तंबाकू के बड़े स्टॉक पर कार्रवाई की है। कई मामलों में नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि गंभीर स्वच्छता उल्लंघनों के चलते कुछ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित या कारोबार बंद करने की कार्रवाई की गई। छत्रपति संभाजीनगर विभाग में धाराशिव, परभणी, वैजापुर और सिल्लोड सहित कई स्थानों पर कार्रवाई हुई। धाराशिव में शिवशंकर खवा पेठा उद्योग एवं बिक्री केंद्र से भेसल के संदेह में 249 किलो खवा, कीमत 57,270 रुपये जब्त किया गया। तुलजापुर में विभिन्न खवा भट्टियों और मिठाई प्रतिष्ठानों से खवा, पेड़ा और कलाकंद भी जब्त किए गए। परभणी जिले के जितूर और औद्योगिक क्षेत्र में मे. मयूर एजेंसीज, मे. अथर्व एजेंसीज, मे. वरद ऑयल इंडस्ट्रीज और मे. मोती नमकीन प्रा. लि. पर कार्रवाई की गई। यहां खाद्य तेल और सेव-फरसाण मिश्रण मिलाकर कुल 31,866 किलो माल, जिसकी कीमत करीब 81.71 लाख रुपये बताई गई है, जब्त किया गया। वैजापुर के सिड्डीविनायक ट्रेडर्स से 343 किलो गाय का घी, कीमत 2.72 लाख रुपये और

सिल्लोड के न्यू भारत बेकरी से 1,013 किलो टोस्ट, स्पेशल टोस्ट और पिस्ता रोस्ट, कीमत करीब 1.29 लाख रुपये, जांच के तहत दर्ज किए गए। नागपुर विभाग में हुडकेस्वर रोड स्थित चंद्रभागा ट्रेडर्स से अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे गए 1,078.40 लीटर रिफाईंड सोयाबीन तेल, कीमत 1.81 लाख रुपये प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित। वहीं चंद्रपुर जिले के वरोरा स्थित जयंत स्वीट मार्ट से 49 किलो खवा, कीमत 19,600 रुपये जब्त किया गया। कोकण विभाग के भिवंडी में विराज एंटरप्राइज पर कार्रवाई के दौरान करीब 1.27 करोड़ रुपये का खाद्य तेल और चाय की कार्रवाई की गई। छत्रपति संभाजीनगर विभाग में धाराशिव, परभणी, वैजापुर और सिल्लोड सहित कई स्थानों पर कार्रवाई हुई। धाराशिव में शिवशंकर खवा पेठा उद्योग एवं बिक्री केंद्र से भेसल के संदेह में 249 किलो खवा, कीमत 57,270 रुपये जब्त किया गया। तुलजापुर में विभिन्न खवा भट्टियों और मिठाई प्रतिष्ठानों से खवा, पेड़ा और कलाकंद भी जब्त किए गए। परभणी जिले के जितूर और औद्योगिक क्षेत्र में मे. मयूर एजेंसीज, मे. अथर्व एजेंसीज, मे. वरद ऑयल इंडस्ट्रीज और मे. मोती नमकीन प्रा. लि. पर कार्रवाई की गई। यहां खाद्य तेल और सेव-फरसाण मिश्रण मिलाकर कुल 31,866 किलो माल, जिसकी कीमत करीब 81.71 लाख रुपये बताई गई है, जब्त किया गया। वैजापुर के सिड्डीविनायक ट्रेडर्स से 343 किलो गाय का घी, कीमत 2.72 लाख रुपये और



में चैतन्य किराणा हार्डवेयर से Sunrise ब्रांड की 87 किलो भगर, कीमत 6,960 रुपये, निकुष्ट और भेसलयुक्त होने के संदेह में जब्त की गई। मुंबई में कांदिवली पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में FDA की टीम ने विभिन्न फरसाण और मिठाई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। कांदिवली पूर्व के श्री सदगुरु फूड्स से रंग के संदेह वाले वेफर्स, में तेल ऑलिव ऑयल न होकर पूरी तरह ग्राउंडनट ऑयल पाए जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद 11,779 लीटर खाद्य तेल और 2,850 किलो चाय का स्टॉक जब्त किया गया। पुणे विभाग में बावधन, कसबा पेठ और बिबवेवाडी क्षेत्र में नियंत्रित तापमान के अभाव में परिवहन और भंडारण के संदेह में 9,000 किलो पनीर और 440 किलो खवा जब्त किया गया। माकेंट यार्ड स्थित 3D Masale & DryFruits से चाय और फ्लेवर्ड ड्रिंक कॉन्सन्ट्रेट समेत 77.75 किलो खाद्य पदार्थ तथा पौड रोड, चांदणी चौक स्थित Suryam Enterprises से 9,888 लीटर खाद्य तेल जब्त किया गया। अहिल्यानगर जिले

ठाणे के कई इलाकों में 36 घंटे पानी बंद, 22 अक्टूबर आधी रात से शटडाउन

ठाणे। ठाणे महानगरपालिका (TMC) ने शहर के कई प्रमुख इलाकों में 36 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रखने की घोषणा की है। यह शटडाउन गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे से शुरू होकर शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 की दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा। नगर निगम के अनुसार, मानसून के बाद अपेक्षा से कम बारिश, अल नीनो की स्थिति और मानसून के जल्दी समाप्त होने के कारण राज्य सरकार ने पानी की आपूर्ति में 10 प्रतिशत कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) के जंभूल जल उपचार संयंत्र से जलापूर्ति इस अवधि में अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस शटडाउन का सबसे अधिक असर दिवा और कलवा वार्ड समिति क्षेत्रों में होगा, जहां सभी इलाकों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। मुंन्ना वार्ड समिति के अधिकांश क्षेत्रों में भी जलापूर्ति प्रभावित रहेगी, हालांकि वार्ड क्रमांक 26 और 31 के कुछ हिस्सों को इससे बाहर रखा गया है। वागले वार्ड समिति में रूपदेवी मानपाड़ा वार्ड समिति के अंतर्गत कोलशेर खालका गांव में भी पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। ठाणे महानगरपालिका ने नागरिकों से आवश्यक पानी पहले से संग्रहित करने और उसका संयमित उपयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शनिवार दोपहर जलापूर्ति बहाल होने के बाद भी प्रभावित क्षेत्रों में एक-दो दिन तक पानी का दबाव कम रह सकता है।

पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम फडणवीस ने 154 शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि



संवाददाता

मुंबई। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागवांग पुलिस मुख्यालय स्थित स्मृति स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को देशभर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कर्तव्य निभाते हुए वीरगति प्राप्त 36 पुलिस अधिकारियों और 118 पुलिस कर्मियों सहित कुल 154 शहीदों की स्मृति को नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष अधिवक्ता राहुल नावेंकर, मुंबई उपनगर के सह-पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, महापौर ऋतु तावडे, गृह विभाग

की अपर मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते और मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन पुलिस मुख्यालय स्थित स्मृति स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस बल की ओर से शहीदों के सम्मान में बंदूकों से सलामी दी गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस दौरान विभिन्न देशों के दूतावासों से आए आमंत्रित प्रतिनिधियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी मुलाकात की।



में चैतन्य किराणा हार्डवेयर से Sunrise ब्रांड की 87 किलो भगर, कीमत 6,960 रुपये, निकुष्ट और भेसलयुक्त होने के संदेह में जब्त की गई। मुंबई में कांदिवली पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में FDA की टीम ने विभिन्न फरसाण और मिठाई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। कांदिवली पूर्व के श्री सदगुरु फूड्स से रंग के संदेह वाले वेफर्स, भुजिया और शेजवान स्टिक्स मिलाकर 22,045 रुपये का माल जब्त किया गया। कांदिवली पश्चिम के श्री गणेश फरसाण एंड स्वीट मार्ट से रंग पाए जाने पर जलेबी और महाराजा हलवा, कीमत 3,150 रुपये, जब्त कर मौके पर नष्ट किया गया। प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। जालना में एक संदिग्ध आयरशर वाहन से 53.25 लाख रुपये का प्रतिबंधित पानमसाला और सुगंधित तंबाकू मिला। वाहन, मोबाइल और GPS उपकरण सहित कुल करीब 83.35 लाख रुपये का माल जब्त किया गया। मुंबई में टाटा इंड्रा वाहन से 7.06 लाख रुपये का प्रतिबंधित स्टॉक और 3

लाख रुपये का वाहन जब्त कर संबंधित आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। FDA ने होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और कैटीन में गंभीर स्वच्छता उल्लंघनों पर भी कार्रवाई की। मुंबई में Arabian Shawarma Cafe & Fast Food, Nath Fast Food, NAIROON FIRE Cloud Kitchen और Bikaner Sweets and Namkin के खिलाफ लाइसेंस निलंबन या कारोबार बंद करने की कार्रवाई की गई। जांच में अस्वच्छ किचन, खराब ड्रेनेज, जंग लगे रैक और बर्तन, तापमान रिकॉर्ड में कमी, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाणपत्र न होना तथा मिठाई में अनधिकृत रंग के इस्तेमाल जैसी खामियां सामने आईं। FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने नागरिकों से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता या अनियमितता संबंधी शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-222-365 और विभाग के शिकायत पोर्टल 83.35 लाख रुपये का माल जब्त किया गया। मुंबई में टाटा इंड्रा वाहन से 7.06 लाख रुपये का प्रतिबंधित स्टॉक और 3

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: आरोपियों से पूछताछ के लिए पुलिस को 31 अक्टूबर तक कस्टडी

संवाददाता

मुंबई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को बुधवार को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपियों की पहचान फूल सिंह, ऋतिक कुमार और रेहान अंसारी के रूप में हुई है। तीनों को बुधवार तड़के राजस्थान के कोटा से मुंबई लाया गया। कोर्ट में पेश किए जाने से पहले उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी और अभियोजन पक्ष ने तीनों की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए कहा कि फायरिंग की साजिश, आरोपियों की भूमिका और वारदात से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में लिए उनसे आगे पूछताछ जरूरी है। पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में हरियाणा और दिल्ली से पांच अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तीन पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। इन आरोपियों को भी आगे की जांच के लिए मुंबई लाया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त राज तिलक रौशन के अनुसार, दो पुरुष आरोपियों की कथित भूमिका अमृतसर से हथियार हासिल करने और उन्हें मुंबई

कोटा से मुंबई लाए गए फूल सिंह, ऋतिक कुमार और रेहान अंसारी; हथियार और मोबाइल फोन अब भी बरामद नहीं



पहुंचाने से जुड़ी थी। पुलिस का दावा है कि हथियार मुंबई तक पहुंचाने के लिए दो महिलाओं को कूरियर के रूप में इस्तेमाल किया गया। इन महिलाओं ने कथित तौर पर हथियार शूटर्स को सौंपे, जिनका इस्तेमाल 18 अक्टूबर की फायरिंग में किया गया। पुलिस के अनुसार, तीसरे पुरुष आरोपी पर शूटर्स को लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने का आरोप है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार अब तक बरामद नहीं किए जा सके हैं। पुलिस ने यह भी दावा किया कि वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन नष्ट कर दिए गए हैं। जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फोन किस तरह

नष्ट किए गए और उनसे जुड़ा डिजिटल डेटा किस हद तक हासिल किया जा सकता है। रेहान अंसारी की ओर से पेश अधिवक्ता अजिंक्य मिरगल ने पुलिस हिरासत बढ़ाने का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी को पहले ही ट्रिजिट रिमांड पर कोटा से मुंबई लाया जा चुका है और मामले में कई अन्य गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, इसलिए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलें स्वीकार करते हुए तीनों आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब हथियारों की बरामदगी, मोबाइल फोन, फंडिंग, रेकी और पूरे नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की जांच आगे बढ़ाएगी।

नेरुल स्टेशन के बाहर चाकू से घायल युवती की मौत

संवाददाता

नवी मुंबई। नेरुल रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार सुबह चाकू से हुए हमले में गंभीर रूप से घायल 21 वर्षीय युवती की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद नेरुल पुलिस अब पहले दर्ज हत्या के प्रयास के मामले को हत्या के मामले में बदलने की कार्रवाई करेगी। मृतका की पहचान सादिया जहीर शेख (21) के रूप में हुई है। वह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करती थी। हमले में उसकी पीट, पेट, छाती और गर्दन पर कई चाकू के घाव आए थे। उसका इलाज वाशी स्थित सरकारी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा था, जहां बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। मामले में आरोपी दानिशा मोहम्मद अंसारी (27) को पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। वह वडाला के एंटीप हिल इलाके का रहने वाला है। नेरुल थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय कांबले के अनुसार, पीड़िता की मौत के बाद हत्या के प्रयास की धाराओं के स्थान पर हत्या का आरोप जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की आगे की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक, सादिया और दानिशा पिछले करीब चार साल से रिश्ते में थे और दोनों ने शादी का फैसला भी किया था।

मुंबई में आपातकालीन मदद के लिए फायर ब्रिगेड ने जारी किए पांच वैकल्पिक मोबाइल नंबर

मुंबई। आग, इमारत गिरने, सड़क दुर्घटना, पेड़ गिरने, पानी में डूबने और अन्य आपातकालीन घटनाओं के दौरान नागरिकों को समय पर मदद मिल सके,



परिवारों को भी इसकी जानकारी दी गई थी। हालांकि पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच विवाद बढ़ गए थे। आरोपी है कि दानिशा को संदेह था कि सादिया का किसी अन्य युवक से भी संबंध है। पुलिस के अनुसार, इसी संदेह को लेकर आरोपी ने पहले भी सादिया के साथ मारपीट की थी। इन घटनाओं को लेकर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन और एंटीप हिल पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। लगातार परेशान किए जाने के बाद सादिया ने उससे दूरी बनाने का फैसला किया था। सोमवार सुबह सादिया काम पर जाने के लिए जीटीबी नगर रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर नेरुल पहुंची थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी उसका पीछा करते हुए नेरुल तक पहुंचा।

इसके लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मुंबई फायर ब्रिगेड ने 101 आपातकालीन नंबर के साथ पांच वैकल्पिक मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड की ओर से जारी वैकल्पिक नंबर 9076333101, 9076333102, 9076333103, 9076333104 और 9076333105 हैं। 101 नंबर की सेवा में किसी तकनीकी खराबी के कारण संपर्क बाधित होने की स्थिति में नागरिक इन नंबरों का

सुबह करीब 6:45 बजे, जब वह नेरुल रेलवे स्टेशन के पूर्वी प्रवेश द्वार के बाहर बस स्टॉप के पास पहुंची, तब उस पर चाकू से हमला किया गया। आरोप है कि दानिशा ने सादिया की पीट, पेट, छाती और गर्दन पर पांच से छह बार किए और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद नेरुल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को वाशी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सादिया की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 109(1), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया था। अब उसकी मौत के कारण कभी-कभी सेवा प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए आपातकालीन संपर्क व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं।

उपयोग कर सकेंगे। फायर ब्रिगेड के अनुसार, 101 आपातकालीन टेलीफोन सेवा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। तकनीकी खराबियों और मरम्मत के लिए उपलब्ध मानव संसाधन की कमी के कारण कभी-कभी सेवा प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए आपातकालीन संपर्क व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं।

मुंबई एयरपोर्ट पर 3.47 करोड़ का सोना जब्त अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के पांच सदस्य गिरफ्तार

दुबई से आए यात्रियों ने एयरोब्रिज पर एयरपोर्ट कर्मचारी को सौंपी थी खेप, 19 गोल्ड बार और चार छोटे टुकड़े बरामद



मुंबई। अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक संयोजित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 2,317 ग्राम 24 कैरेट सोना, जिसकी कीमत करीब 3.47 करोड़ रुपये बताई गई है, जब्त किया गया। मामले में कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार, सोमवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दुबई से मुंबई आने वाले दो यात्रियों अकील अख्तर मीर और शादाब सलीम बगदादी पर टर्मिनल-2 पर उतरने के बाद नजर रखी जा रही थी। दोनों बिना कोई सामान घोषित किए कस्टम्स ग्रीन चैनल से बाहर निकल गए, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें एंजिंट गेट के पास रोक लिया। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने किसी प्रतिबंधित या अघोषित सामान को साथ लाने से इनकार किया। हालांकि आगे की पूछताछ में कथित तस्करी नेटवर्क की जानकारी सामने आई। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों यात्रियों ने दुबई से सोने की ईंटें लाने और उन्हें एयरपोर्ट की आंतरिक जांच से बचाने के लिए सीधे

अंदर सोने की 19 ईंटें और चार छोटे सोने के टुकड़े बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार, जब्त सोने का कुल वजन 2,317 ग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत 3.47 करोड़ रुपये है। \जांच एजेंसी का दावा है कि पूछताछ में पांचों आरोपियों ने कथित तौर पर नेटवर्क में अपनी अलग-अलग भूमिकाओं—कैरियर, हैंडलर और रिसीवर—के बारे में जानकारी दी। DRI अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था, सोने की खेप किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी और इसके तार किन अन्य देशों या शहरों से जुड़े हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

PDA Unity to Strengthen SP’s Prospects in UP MLC Polls, Says Pal

PRAYAGRAJ: The BJP has no answers to the public's questions on issues like unemployment, paper leaks, inflation, farmers' problems, and vote theft. The BJP is alarmed by the PDA's unity. The people of the state are ready to remove the BJP from power on these issues. Speaking to the media on Wednesday at a hotel in Prayagraj's Civil Lines, Samajwadi Party state president Shyam Lal Pal said, 'Samajwadi Party candidates will win the most seats in the state's Teachers' and Graduates' Legislative Council elections. He said that the party is contesting the elections on public issues and that the unity of the PDA is the SP's strength.' There is a possibility of SP lead-



ers being put under house arrest before the polling: Dr. Mansingh Yadav, the Samajwadi Party candidate for the Graduate Legislative Council elections, accused the BJP of conspiring with the administration in the election. He expressed apprehension that attempts could be made to confine influential Samajwadi Party leaders to their homes on the day of voting. He also alleged that attempts could be made

to intimidate and threaten voters. Dr. Yadav expressed apprehension that an attempt could be made to replicate the Milkipur situation. Dr. Mansingh Yadav stated that the Samajwadi Party is firm on issues related to education and employment. He stated that preventing paper leaks, giving respectable status to Shikshamitras, implementing the Advocates Protection Act, paying honorarium

to instructors and unaided teachers, and streamlining the examination calendar are among the party's priorities. He claimed that voter sentiment favors the SP on these issues. Many leaders were present in the press conference: During this, many party leaders and officials including SP District President Anil Yadav, Metropolitan President Syed Iftekhar Husain, MLA Vijma Yadav, Hakim Lal Bind, Geeta Shastri and Sandeep Patel, former MLA Haji Mujtaba Siddiqui, Haji Parvez Ahmed, Satyaveer Munna, Amarnath Maurya, party spokesperson Dan Bahadur Madhur, Ravindra Yadav Advocate and Engineer Jagdish Yadav were present.

Vijay Salutes Police Personnel for Their Courage and Sacrifice

CHENNAI: Police Commemoration Day is an occasion to remember personnel who died protecting the nation and recognise the dedication of those serving the public, Tamil Nadu Chief Minister Vijay said on Wednesday. Paying homage to fallen officers, Vijay said their sacrifices reflected the courage and commitment required to preserve peace, maintain law and order and safeguard citizens across the country. In a social media message, the Chief Minister recalled the sacrifice of 10 Central Reserve Police Force personnel who lost their lives defending the country at the Ladakh border in 1959. Remembering their service, he extended his tribute to all police personnel who had died while carrying out their



responsibilities, saying their contribution deserved enduring respect and gratitude. 'On Police Commemoration Day, which honours their historic sacrifice, we salute all police personnel who laid down their lives while performing the noble duty of maintaining peace and law and order across the country,' he said. Vijay also praised serving personnel for responding to emergencies with courage and vigilance, often under difficult circumstances and without predictable working

hours. Natural disasters, accidents, criminal activity and threats to public safety placed varied demands on the force, he said, commending officers for their readiness to respond whenever needed. Describing the police as the nation's protective fortress, the Chief Minister said their work frequently required them to serve without watching the clock or getting adequate rest. Their sustained efforts helped protect communities and uphold public order, he said, calling for appreciation of the responsibilities they shouldered. His message highlighted both the risks associated with policing and the dedication needed to meet everyday demands, from preventing crime to assisting people during emergencies.

Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu Calls for Technology-Driven Policing

AMARAVATI: Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu on Wednesday called on police personnel to adopt advanced technologies, including artificial intelligence, data analytics and drones, to prevent crime and improve investigations, while emphasising humane treatment of victims and effective maintenance of law and order. Addressing police personnel on Police Commemoration Day at the sixth Andhra Pradesh Special Po-

lice Battalion in Mangalagiri, Naidu paid floral tributes to police martyrs at the Amar Jawan Memorial. He said effective law and order was essential for the state's development, attracting investments and ensuring public welfare. Naidu said the sacrifices of police personnel who laid down their lives in the line of duty should be remembered as a responsibility rather than merely an expression of sympathy. Describing policing as a noble profession,



he said personnel risked their lives to protect the public and often sacrificed time with their families while maintaining security during festivals, VIP visits and other events. Empha-

sing technology-led policing, the Chief Minister said CCTV cameras could help identify crimes, while data analysis could reveal facts and strengthen investigations. He urged the Andhra Pradesh Police to emerge as a national leader in technology-driven policing and suggested greater use of drones for surveillance and other purposes. Naidu stressed that every person approaching a police station should be treated with respect and given a patient

hearing. The police uniform should reassure victims, while criminals should fear the law, he said. He directed police personnel to take strict action against rowdies, anti-social elements and those committing offences under the guise of politics. Warning about the growing threat of cyber-crime, Naidu said fraudsters were stealing people's lifetime savings through phone calls, links and messages. He called for stronger efforts to ensure women's

safety, curb drug abuse and ganja trafficking, and reduce road accidents. He also congratulated the EAGLE anti-narcotics team for its efforts to tackle drugs. The Chief Minister said law and order, development, employment and public happiness were interconnected, adding that industrialists would hesitate to invest in areas affected by unrest and insecurity. He also congratulated the Counter Intelligence wing for uncovering conspiracies that

posed a threat to national security. Naidu urged police personnel to maintain physical and mental fitness and manage work-related stress through yoga, meditation and other activities. He said the ultimate objective of policing was to ensure that citizens could sleep peacefully and their property remained protected. He assured the families of police martyrs that the government would support them and work for the welfare of police personnel.

मस्क यांनी युकेनच्या स्टारलिंग नेटवर्कचा वेग कमी करण्याचे दिले आदेश



वॉशिंग्टन: सध्या रशिया विरुद्धच्या युद्धात युकेनला अमेरिकेकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे. याचे उदाहरण म्हणजे, एलन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीवर युकेनच्या लष्कराकडून वापरण्यात येणाऱ्या स्टारलिंग उपग्रह इंटरनेट सेवेत अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एका वृत्तानुसार, मस्क यांनी युकेनच्या महत्त्वपूर्ण लष्करी स्टारलिंग नेटवर्कचा वेग जाणूनबुजून कमी करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे युकेनची राजधानी कीवमध्ये खळबळ उडाली. या निष्णयामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासनही आश्चर्यचकित झाल्याचे वृत्तात अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. मात्र, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी स्टारलिंगचा वेग कमी करण्याचे कोणतेही आदेश दिले नाहीत. 'आम्ही कोणतेही निर्देश दिले नाहीत.' स्टारलिंग सेवेत झालेले कोणतेही बदल हे उपग्रह सेवा पुरवठ्याद्वाराच्या करारातील अटीनुसार होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनीही व्हाइट हाऊसने स्टारलिंगचा वेग कमी करण्याचे आदेश दिल्याच्या दाव्यांचे खंडन केले. स्टारलिंग ही स्पेसएक्सची व्यावसायिक सेवा आहे, तर

स्टारशील्ड ही अमेरिकेची लष्करी प्रणाली आहे. स्टारशील्डची सेवा युकेनला उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, युकेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी मस्क यांच्यावर युकेनचा स्टारलिंग सेवेवरील प्रवेश मर्यादित केल्याचा आरोप केला. यामुळे लष्करी मोहिमांवर परिणाम झाल्याचे त्यांनी म्हटले. एका मुलाखतीत झेलेन्स्की म्हणाले, 'ते नेमके काय करत आहेत, याची त्यांना जाणीव होती, हे मी खात्रीने सांगू शकतो. रात्री एक वाजता स्पेसएक्स आणि अमेरिकेने स्टारलिंग सेवा रोखली.' युकेनचे लष्कर देहळणी आणि शत्रूचे ड्रोन रोखण्यासाठी वापरण्यात येणारी ड्रोन यंत्रणा चालवणे, गुप्तचर माहिती गोळा करणे तसेच युद्धभूमीवरील इतर महत्त्वाच्या कार्यांसाठी स्टारलिंगवर अवलंबून आहे. या सेवेत अडथळे निर्माण झाल्याने लष्करी दळणवळण आणि विविध मोहिमांमधील समन्वयावर परिणाम झाला. दरम्यान, युकेनचे माजी संरक्षणमंत्री मिखाइलो फेडोरोव्ह यांनी नंतर सांगितले की, स्टारलिंगची जोडणी ताशी १६० किलोमीटर वेगापर्यंत बहाल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, स्टारशील्डवरील वेगमर्यादा पूर्णपणे हटवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मस्क यांचे आभार मानतानाच त्यांनी भविष्यातही सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्ली विमानतळावर रोखले, 50 हजारांचा दंड ठोठावल्याचा 'आप'चा दावा

नवी दिल्ली / चंदीगड: पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना दिल्ली विमानतळावर तीन तास रोखण्यात आले होते. तसेच पॅरिसवरून परतल्यावर अधिकाऱ्यांनी मान यांच्यावर ५०,००० रुपयांचा दंडही आकारला, असा दावा 'आप'कडून करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मान यांनी १७ ते २१ ऑक्टोबर दरम्यान पॅरिसमध्ये आयोजित 'एसआयएल पॅरिस २०२६' (SIAL Paris 2026) या आंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार प्रदर्शनात सहभागी झाले होते. दरम्यान केंद्र सरकारच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यांना फ्रान्स दौऱ्यावर जाण्याची परवानगी दिली होती. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे माजी मंत्री सीरम भारद्वाज यांनी 'एक्स'वर एका पोस्टमध्ये



म्हटले आहे की, ज्याप्रमाणे दसऱ्याच्या दिवशी रावणाचा अहंकार नष्ट झाला होता, त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारचा अहंकारही मोडीत काढला पाहिजे. पंजाबमधील आम आदमी पार्टीचे (आप) माध्यम प्रभारी बलतेज पन्नी यांनी या घटनेचा संबंध केंद्र सरकारने मुख्यमंत्री मान यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी वारंवार परवानगी नाकारल्याच्या प्रकरणाशी जोडला आहे. 'एक्स'वर एक व्हिडिओ पोस्ट करत त्यांनी सांगितले की, सुरुवातीला अधिकाऱ्यांनी सामान येण्यास किंवा तपासणीस विलंब झाल्याचे कारण दिले होते.

मात्र, मुख्यमंत्री मान यांचे सामान त्यांच्या वाहनात चढवले जात असताना आणि ते निघण्याच्या तयारीत असतानाच, अधिकाऱ्यांनी त्यांना चलन दिले. यावेळी अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला की, त्यांच्यावर वरिष्ठ स्तरावरून प्रचंड दबाव होता. आपचे नेते बलतेज पन्नी यांनी केंद्र सरकारवर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी भेदभाव केल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, मान पंजाबच्या उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रोत्साहन देण्यासाठी पॅरिसमध्ये आयोजित एसआयएल

फूड ट्रेड एक्झिबिशनमध्ये सहभागी झाले होते. पन्नी यांच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही पॅरिसमधील भारतीय कॉन्सुल जनरल मान यांची भेट घेण्यासाठी आले नाहीत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भगवंत मान यांना फ्रान्सच्या नियोजित दौऱ्यासाठी परवानगी नाकारली होती. कट्टरपंथी गटांकडून असलेल्या धोक्याचा हवाला देत हा निर्णय घेण्यात आला होता. पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्राच्या या निर्णयाला आव्हान दिले. सरकारने असा युक्तिवाद केला की, हा दौरा राजकीय स्वरूपाचा नसून, त्यामागे राज्याचे व्यावसायिक आणि कृषीविषयक हितसंबंध जपण्याचा उद्देश आहे. १६ ऑक्टोबर रोजी पंजाब उच्च न्यायालयाने मान यांना फ्रान्सला जाण्याची परवानगी दिली.

राष्ट्रीय कला प्रदर्शनात महाराष्ट्राच्या तीन कलाकारांचा गौरव



नवी दिल्ली: ललित कला अकादमीच्या ६५ व्या राष्ट्रीय कला प्रदर्शनात महाराष्ट्राच्या तीन कलाकारांनी राष्ट्रीय स्तरावर ठसा उमटवला आहे. रमेश विठ्ठल थोरात, सिद्धार्थ शाहजीराव शिंगाडे आणि प्रितम मधुकर देवसकर यांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. नवी दिल्ली येथील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात ६५ व्या राष्ट्रीय कला प्रदर्शन आणि तिसऱ्या 'प्रिंट बिनाले इंडिया' च्या संयुक्त पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय संस्कृती व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आणि संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव विवेक अग्रवाल यावेळी उपस्थित होते. या सोहळ्यात रमेश विठ्ठल थोरात यांना 'अनटायटल्ड

– II' या तैलचित्रासाठी, सिद्धार्थ शाहजीराव शिंगाडे यांना 'ट्रीज' या मिश्र माध्यमातील कलाकृतीसाठी, तर प्रितम मधुकर देवसकर यांना 'ऑफ टाइम अँड द सिटी' या प्रिंटमेकिंगमधील कलाकृतीसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या राष्ट्रीय कला प्रदर्शनासाठी देशातील २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील २,४९५ कलाकारांच्या एकूण ६,१७५ कलाकृती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातून पहिल्या टप्प्यात निवड समितीने २७० कलाकृतींची प्रदर्शनासाठी निवड केली. त्यानंतर अंतिम निवड प्रक्रियेतून २० उत्कृष्ट कलाकृती राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी निवडण्यात आल्या होत्या. विविध कलामाध्यमांतील त्यांच्या उत्कृष्ट कलाकृतींची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेल्याने महाराष्ट्राच्या कलाप्रतिभेचा गौरव झाला आहे.

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ

(म्हाडाचा घटक)

जाहिर सुचना

मौजे- वांद्रे, ता-अंधेरी येथील न.भू.क्र.२० (१) या मिळकतीवरील गुलमोहर सह. गृह. संस्था (नियो.) या संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत परि-२ मधील अ.क्र. १८३ वरील श्री. जे.रॉम मस्करनस यांच्या ऐवजी श्रीम. कमरुनिसा अलताफ शेख यांचे नाव सामाविष्ट करून पात्रता निश्चित करणेकामीचा अर्ज प्राप्त झाला आहे. सबब सदर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की, उपरोक्त प्रकरणी हरकत असल्यास ८ दिवसांत खालील सही करणार यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी, असे याद्वारे जाहिर असे.

पत्ता : कक्ष क्र.३११, दुसरा मजला, गृहनिर्माण भवन, कलानगर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई -४०० ०५१

करीता/- सक्षम प्राधिकारी तथा भूव्यवस्थापक मुंबई मंडळ

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २२/१०/२०२६

म्हाडा- गृहनिर्माण क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य संस्था

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ

(म्हाडाचा घटक)

जाहिर सुचना

मौजे- वांद्रे, ता-अंधेरी येथील न.भू.क्र.२० (१) या मिळकतीवरील गुलमोहर सह. गृह. संस्था (नियो.) या संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत परि-२ मधील अ.क्र. १८४ वरील श्री. तुकाराम मेस्त्री यांच्या ऐवजी श्री. मुबारक अली अलताफ हुसैन शेख यांचे नाव सामाविष्ट करून पात्रता निश्चित करणेकामीचा अर्ज प्राप्त झाला आहे. सबब सदर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की, उपरोक्त प्रकरणी हरकत असल्यास ८ दिवसांत खालील सही करणार यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी, असे याद्वारे जाहिर असे.

पत्ता : कक्ष क्र.३११, दुसरा मजला, गृहनिर्माण भवन, कलानगर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई -४०० ०५१

करीता/- सक्षम प्राधिकारी तथा भूव्यवस्थापक मुंबई मंडळ

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २२/१०/२०२६

म्हाडा- गृहनिर्माण क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य संस्था

'रामायण' की एडवांस बुकिंग में अच्छी शुरुआत

निर्देशक नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म 'रामायण: भाग 1' ने एडवांस बुकिंग में अच्छी शुरुआत की है। रणबीर कपूर अभिनीत इस फिल्म की बुकिंग दशहरे से शुरू हुई थी। बुधवार दोपहर 12 बजे तक देशभर में इसके 91 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके थे। फिल्म में साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, अरुण गोविल और सनी देओल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक



फिल्म के 3,542 शो के लिए अब तक 91,125 टिकट बिक चुके हैं। इससे करीब 5.35 करोड़ रुपये का एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ है। ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा लगभग 3 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। शहरों के लिहाज से दिल्ली-एनसीआर सबसे आगे है, जहां फिल्म ने करीब 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। मुंबई 1.08 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और पुणे 29.65 लाख रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है। फिल्म की एडवांस

बुकिंग में हिंदी संस्करण का सबसे बड़ा योगदान है। रिपोर्ट के अनुसार, हिंदी संस्करण से करीब 5.07 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है, जो कुल कमाई का लगभग 95 प्रतिशत है। कन्नड़ संस्करण ने 27.11 लाख रुपये कमाए हैं, जबकि तेलुगु संस्करण की कमाई 48,700 रुपये बताई गई है। फिलहाल फिल्म की औसत ऑक्जुपेंसी करीब 12 प्रतिशत है। रिलीज में अभी समय बाकी होने के कारण बुकिंग के आंकड़ों में आगे बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।



फिल्म 'मीठे में क्या है' के ट्रेलर ने बढ़ाई उत्सुकता

नेटफ्लिक्स ने अपनी आगामी फिल्म 'मीठे में क्या है' का ट्रेलर जारी कर दिया है। ऋत्विक् भौमिक और रोहिणी हट्टंगड़ी अभिनीत यह फिल्म पारिवारिक रिश्तों, दिवाली के जश्न हास्य के अंदाज में पेश करती है। फिल्म के जरिए राधिका बंसल तौर निर्देशन की दुनिया में कदम रख रही हैं। अजीत मोहन ने उत्थान कैपिटल के बैनर तले इसका निर्माण किया है। फिल्म में आयशा रजा मिश्रा, अभय कौल, तराना राजा, गौरव के शर्मा और विक्रम बख्शी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक मध्यवर्गीय भारतीय परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां दिवाली मनाने के लिए सभी रिश्तेदार एक छत के नीचे जुटते हैं।

त्योहार की खुशियों और पारिवारिक मेल-मिलाप के बीच उस समय नया मोड़ आता है, जब अचानक एक शादी की घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद घर में चर्चाओं, उलझनों और हलचल का सिलसिला शुरू हो जाता है। ट्रेलर में रोजमर्रा के रिश्तों की नोकझोंक और परिवार के सदस्यों के बीच होने वाली मजेदार घटनाओं की झलक देखने को मिलती है। दिवाली के माहौल और पारिवारिक मनोरंजन से सजी यह फिल्म दर्शकों को हंसी के साथ रिश्तों की कहानी दिखाने का प्रयास करती है। फिल्म का ट्रेलर जारी होने के साथ ही इसकी रिलीज तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। 'मीठे में क्या है' 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

सैफ अली खान की फिल्म में अब नजर नहीं आएंगी प्रियंका चोपड़ा

अभिनेता सैफ अली खान और फिल्ममेकर रितेश बत्रा की आगामी फिल्म में अब प्रियंका चोपड़ा नजर नहीं आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अनाम पीरियड ड्रामा में प्रियंका को मुख्य अभिनेत्री के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन व्यस्त पेशेवर कार्यक्रमों के कारण उन्होंने परियोजना से दूरी बना ली है। इस फिल्म के जरिए पहली बार सैफ और प्रियंका को एक साथ पर्दे पर देखने की उम्मीद कर रहे प्रशंसकों को निराशा हो सकती है। फिल्म की शूटिंग 21 अक्टूबर से मुंबई के भायखला स्थित एक संग्रहालय में शुरू होने की खबर है।



रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंका को मुंबई में होने वाली शूटिंग में शामिल होना था, लेकिन उनकी अन्य पेशेवर प्रतिबद्धताओं के चलते शूटिंग की

तारीखों को लेकर तालमेल नहीं बैठ पाया। सूत्र के मुताबिक, प्रियंका सैफ और रितेश बत्रा के साथ काम करने की इच्छुक थीं। निर्माताओं

ने कार्यक्रम में बदलाव करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बन सकी। इसके बाद अभिनेत्री को फिल्म

छोड़ने का फैसला करना पड़ा। प्रियंका के बाहर होने के बाद निर्माता उनकी जगह किसी दूसरी अभिनेत्री को लेने की तैयारी में जुट गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस भूमिका के लिए दो प्रमुख अभिनेत्रियों से बातचीत की जा रही है और जल्द ही नाम तय किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल निर्देशक रितेश बत्रा सैफ अली खान के साथ फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआती चरण में सैफ अपने हिस्सों की शूटिंग करेंगे। हालांकि, फिल्म की नई अभिनेत्री और अन्य विवरणों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

खून की कमी से लेकर दिल की सेहत तक, मेथी का साग है फायदेमंद

लीवर को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान आदतें

मेथी का साग अपनी खास पहचान रखता है। स्वाद में हल्का कसैलापन लिए मेथी के पत्ते न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सेहत के लिए भी उपयोगी माने जाते हैं। मेथी में विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K, फोलेट, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम और कॉपर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के सामान्य कामकाज और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषण मिल सकता है। मेथी के पत्तों में मौजूद फाइबर और अन्य बायोएक्टिव कंपाउंड भी इसे पौष्टिक आहार का हिस्सा बनाते हैं। इसे सब्जी, दाल, परांठे या रोटी के आटे में मिलाकर कई तरह से खाया जा सकता है। हालांकि, इसके सेवन से किसी बीमारी का इलाज होने की गारंटी नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं मेथी का



साग खाने से सेहत को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं और इसे डाइट में शामिल करने का सही तरीका क्या है।
मेथी साग से सेहत को होने वाले लाभ
खून की कमी से बचाव
डाइट एक्सपर्ट्स के अनुसार, मेथी साग खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। इसके पत्तों में आयरन और विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर को हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाकर हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने में मदद करता है।

ब्लड शुगर करता है कंट्रोल
आपको बता दें, मेथी साग खाने से शरीर में खून की कमी के अलावा ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है। मेथी के पत्तों में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर और बायो-एक्टिव कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा करते हैं। यह इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार कर इंसुलिन स्याइक को रोकता है।
स्किन और बालों के लिए बड़ा फायदेमंद
यह स्किन और बालों के लिए भी बड़ा फायदेमंद बताया गया है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट और

लेसिथिन होते हैं, जो स्किन की समस्याओं जैसे मुहांसे और दाग-धब्बे को कम करने और बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। अगर आप मुहांसे और दाग-धब्बे के साथ झड़ते बालों से परेशान है तो आप अपनी डाइट में मेथी साग जरूर शामिल करें।
कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा असरदार
मेथी साग का सेवन कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा असरदार बताया गया है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और सैपोनिन शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है।
मेथी का सेवन कैसे करें?
मेथी के पत्तों को ज्यादा उबालने या ज्यादा पकाने से बचें ताकि इसके हीट सेंसिटिविटी विटामिन C और फोलेट बने रहते हैं। इसे हल्की भाजी, दाल, परांठे/रोटी के आटे में मिलाकर, या सूप/स्मूदी के रूप में ले सकते हैं।

लीवर हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है, इसलिए इसकी सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए किसी खास डिटॉक्स ड्रिंक पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने लीवर की सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, तो इसके लिए अपनी डेली लाइफस्टाइल और रोजाना की खान-पान की आदतों पर ध्यान दें। संतुलित भोजन, डेली एक्टिविटी और शराब का सेवन न करना जैसी आदतें लीवर की सेहत को ठीक रखती हैं।
खाने की थाली को संतुलित रखें
रोज के भोजन में सब्जियां, फल, साबुत अनाज और पर्याप्त प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें। दाल, चना, मूंग, सोया, अंडे और दूसरे पौष्टिक प्रोटीन को अपनी जरूरत के अनुसार भोजन का हिस्सा बनाएं। बहुत ज्यादा मीठे और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ को सीमित करें।
मीठे पेय कम करें
कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड ड्रिंक और



बहुत ज्यादा चीनी वाले दूसरे ड्रिंक्स का नियमित सेवन से बचना चाहिए। NIDDK के अनुसार ज्यादा मात्रा में शर्करा, खासकर मीठे पेय और जूस में मौजूद फ्रुक्टोज, फैटी लीवर के जोखिम को बढ़ा सकता है।
रोज थोड़ा एक्टिव रहें
नियमित शारीरिक गतिविधि लीवर की सेहत के लिए फायदेमंद होती है। तेज चलना, साइकिल चलाना व स्विमिंग जैसी एक्टिविटी को दिनचर्या में शामिल करें। सामान्य स्वस्थ वयस्क के लिए कम से कम 150 मिनट प्रति सप्ताह की एक्टिविटी होनी चाहिए।

के जरिए धीरे-धीरे वजन कम करना चाहिए, इससे लीवर में जमे अतिरिक्त फैट को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन तेजी से वजन घटाने से बचना चाहिए।
बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट न लें
हर हर्बल या नेचुरल सप्लीमेंट लीवर के लिए सुरक्षित नहीं होता है। कुछ हर्बल उत्पाद लीवर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी सप्लीमेंट, हर्बल प्रोडक्ट या हेल्थ संबंधी प्रोडक्ट को लंबे समय तक लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
पानी और अच्छी नींद लें
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और नियमित, संतुलित दिनचर्या बनाए रखना सामान्य स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसके अलावा अच्छी और पर्याप्त नींद लें। साथ ही लीवर साफ करने के लिए किसी खास जूस, काढ़े या डिटॉक्स प्रोडक्ट को अवॉयड करें। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी डाइट और स्वस्थ जीवनशैली जरूरी है।

ब्लड की जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन ऐसे खोजें ब्लड बैंक

मेडिकल इमरजेंसी में हर सेकंड बेहद अहम होता है। खासकर जब किसी मरीज को अचानक खून की जरूरत पड़ जाए, तब सही समय पर सही ब्लड ग्रुप उपलब्ध कराना परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। ऐसी स्थिति में लोग अक्सर आसपास के अस्पतालों, ब्लड बैंकों और परिचितों से संपर्क करना शुरू कर देते हैं। कई बार एक ही ब्लड ग्रुप की तलाश में अलग-अलग जगह फोन करने या अस्पतालों के चक्कर लगाने में काफी समय निकल जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में यही देरी मरीज के परिवार की परेशानी को और बढ़ा सकती है। हालांकि, आज के डिजिटल दौर में ब्लड की उपलब्धता से जुड़ी शुरुआती जानकारी हासिल करना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। भारत सरकार का **e-RaktKosh** डिजिटल

प्लेटफॉर्म लोगों को घर बैठे देश के अलग-अलग ब्लड बैंकों में उपलब्ध ब्लड और विभिन्न ब्लड कंपोनेंट्स की जानकारी खोजने की सुविधा देता है। यानी अगर आपको किसी खास ब्लड ग्रुप की जरूरत है, तो आप ऑनलाइन यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके आसपास या किसी संबंधित इलाके के ब्लड बैंक में उस ग्रुप का स्टॉक उपलब्ध है या नहीं। इस सुविधा की मदद से मरीज के परिजन जरूरत के समय बिना हर ब्लड बैंक में अलग-अलग फोन किए शुरुआती जानकारी हासिल कर सकते हैं। खासतौर पर किसी इमरजेंसी में जब समय कम हो और तुरंत सही जगह पहुंचना जरूरी हो, तब इस तरह की ऑनलाइन सुविधा काफी मददगार साबित हो सकती है। इसके जरिए ब्लड ग्रुप के साथ-साथ जरूरत के अनुसार प्लाज्मा,



प्लेटलेट्स और अन्य ब्लड कंपोनेंट्स की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी भी देखी जा सकती है। हालांकि, ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई देने वाली उपलब्धता को अंतिम पुष्टि नहीं मानना चाहिए। अस्पतालों और ब्लड बैंकों में ब्लड की मांग और स्टॉक लगातार बदलता रहता है। इसलिए e-RaktKosh पर किसी ब्लड ग्रुप का स्टॉक दिखाई देने के बाद संबंधित ब्लड बैंक या अस्पताल से फोन पर संपर्क करके उपलब्धता की दोबारा पुष्टि करना

जरूरी है। साथ ही ब्लड लेने के लिए जरूरी दस्तावेज, प्रक्रिया, समय और अस्पताल से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के बारे में भी पहले जानकारी ले लेना बेहतर रहेगा। ऐसे में अगर आपके परिवार में कभी किसी को अचानक ब्लड की जरूरत पड़ जाए, तो घबराने के बजाय e-RaktKosh जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से आसपास उपलब्ध विकल्पों की जानकारी हासिल की जा सकती है। पहले से इस सुविधा के बारे में जानकारी होने

पर इमरजेंसी के समय सही ब्लड बैंक तलाशने में लगने वाला समय कम किया जा सकता है और जरूरत के मुताबिक जल्द से जल्द संबंधित अस्पताल या ब्लड बैंक से संपर्क किया जा सकता है।
क्या है e-RaktKosh पोर्टल?
e-RaktKosh के बारे में बताएं तो यह एक केंद्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो देशभर के ब्लड बैंकों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। इसके जरिए यूजर्स अलग-अलग जगहों पर उपलब्ध ब्लड, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स समेत अन्य कंपोनेंट्स की जानकारी तलाश कर सकते हैं। वहीं इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एक-एक ब्लड बैंक में जाकर या कई जगह फोन करके उपलब्धता पूछने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। आप एक ही प्लेटफॉर्म पर जरूरत के हिसाब से जानकारी देख सकते हैं।

घर बैठे ऐसे चेक करें Blood Stock
e-RaktKosh पर ब्लड की जानकारी देखना काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। इसके बाद होमपेज पर मौजूद Blood Availability Search विकल्प चुनें। वहीं अब आपको अपनी जरूरत के मुताबिक राज्य, जिला, ब्लड ग्रुप और ब्लड कंपोनेंट जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। सारी डिटेल भरने के बाद Search पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर संबंधित इलाके के ब्लड बैंकों की सूची दिखाई दे सकती है। यहां उपलब्ध स्टॉक से जुड़ी जानकारी देखकर आप अपनी जरूरत के हिसाब से नजदीकी विकल्प तलाश सकते हैं।
स्टॉक दिखे तो पहले फोन पर करें कंफर्म
जानकारी मिलने के बाद कहा जाता

है कि कॉल कर के बात जरूर करें क्योंकि अस्पतालों में ब्लड की मांग लगातार बदलती रहती है। इसलिए पोर्टल पर स्टॉक उपलब्ध दिखाई देने के बावजूद ब्लड बैंक या अस्पताल को फोन करके उपलब्धता की पुष्टि कर लेना बेहतर रहता है। ऐसे में अगर जरूरत का ब्लड उपलब्ध है तो बिना अनावश्यक देरी किए संबंधित ब्लड बैंक या अस्पताल से संपर्क करें। साथ ही ब्लड लेने के लिए जरूरी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट और अस्पताल की जरूरतों की जानकारी पहले ही पुछ लें। पहले जानकारी लेने से इमरजेंसी के समय सही जानकारी और कुछ मिनटों की बचत हो सकती है। इसलिए e-RaktKosh जैसी सरकारी डिजिटल सुविधा के बारे में पहले से पता होना आपके और आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

